मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

2019 की और बढ़ते फेंकू मोदी

सत्ता मांगे रणबीर 3
सीक्रेट रॉफेल 4
रेंगता मीडिया 5
बीमार आयुष्मान 8

वर्ष 31 अंक -35 फ़रीदाबाद 26 अगस्त - 01 सितम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2.50

धर्म की आड़ में चलता एक मुनाफा संस्थान

घोटालों की पढ़ाई के लिये बेहतरीन डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज

फ़रीदाबाद (म. मो.) आर्य समाज के प्रवर्तक महार्षि दयानंद के नाम पर चलने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था डीएवी कॉलेज प्रबन्ध समिति ने डीएवीआईएम के नाम से यहां एनआईटी के एनएच-3 में एक कॉलेज खोल रखा है। कहने को तो इसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक इस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट है, परन्तु यह कॉलेज घोटालों से इस कदर घिरा पड़ा है कि जिस दिन कोई ढंग की सरकार एवं अधिकारी आ गये तो इस घोटाला घर को न केवल ताला लग जायेगा बल्कि कइयों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें भी दर्ज होंगे। इस सबके बावजूद इस कॉलेज का चलना किसी चमत्कार से कम नहीं। घोटालों के बावजूद कॉलेज को चलाये रखने की चमत्कारिक तकनीक सीखने के लिये, जाहिर है, यह एक बेहतरीन कॉलेज है।

एमबीए, बीबीए व कई तरह की बीसीए व एमसीए की पढाई कराने का दावा करने वाले इस संस्थान को मान्यता दे रखी है एआईसीटीई (ऑल इंडिया काऊंसिल ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन ने। काऊंसिल में बैठे रिश्वतखोर अधिकारियों ने वैसे तो इस कॉलेज के तमाम घोटालों की ओर से आंखें मूंद रखी हैं, परन्तु **'मज़दूर मोर्चा'** 27 मई-2 जून 2018 के

अंक में 'डिग्री की दुकान बना अवैध डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज! आधी अधूरी फैक्ल्टी, क्लर्क बन बैठी प्रिंसिपल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में घोटालों का विवरण होने के बाद काऊंसिल ने अयोग्य एवं काम चलाऊ प्रिंसिपल की तैनाती को लेकर इस कॉलेज को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया था। प्रबन्धन ने हाथ-पैर जोड़ कर 6 माह की मोहलत मांगी तो काऊंसिल ने 3 माह यानी 12 अक्तूबर 2018 तक का समय दे दिया। इस तारीख तक प्रबन्धन को एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी।

इस दबाव में प्रबन्धन ने तुर्त-फुर्त 11 जुलाई को प्रिंसिपल पद के लिये विज्ञापन जारी करके योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं। विदित है कि फ़िलहाल नीलम गुलाटी इस कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं जो पिछले करीब 5 साल से चली आ रही हैं। नीलम गुलाटी इसी कॉलेज में फ़ीस क्लर्क होती थी। वांछित योग्यता न होने के चलते एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक ने इन्हें लेक्चरार/सहायक प्रोफ़ेसर पद के लिये एप्रूवल देने से मना कर दिया था। क्योंकि एम कॉम में इनके नम्बर मात्र 58 प्रतिशत थे जबकि कम से कम 60 प्रतिशत चाहिये। इसके साथ एमबीए भी 60 प्रतिशत से पास होनी चाहिये तथा पीएचडी भी होनी चाहिये। नीलम न तो एमबीए है न पीएचडी। 1996 में इन्होंने आईसी डब्लू ए की डिग्री प्राप्त की लेकिन वह भी 59 प्रतिशत नम्बरों से। फ़िर इसी कॉलेज (डीएवीआईएम) से 2010 में लेटरल एमबीए तत्कालीन प्रिंसिपल एन के शर्मा ने जैसे-तैसे करा दी और नम्बर भी खूब सारे (77 प्रतिशत) दिला दिये। पीएचडी के लिये आगरा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन भी अब करा लिया है।

मजे की बात यह है कि सन् 1996 से ये साहिबा यहीं नौकरी भी करती रही और इसी कॉलेज से डिग्रियां भी लेती रहीं। सवाल उठता है कब तो यह नौकरी करती थीं और कब पढाई ? लेकिन सब चलता है। हाथ में डिग्री होनी चाहियें असली हो या नकली कौन पूछता है ? अब इन्ही फ़र्जी डिग्रियों के आधार पर नीलम गुलाटी ने भी प्रिंसिपल पद के लिये आवेदन कर दिया है। प्रबन्धन कमेटी का एक अति प्रभावशाली प्रबोध महाजन किसी भी कीमत पर नीलम को ही स्थाई प्रिंसिपल बनाने पर उतारू है। उन्हें इनमें क्या खूबी दिखाई दे रही है यह तो वही जानें।

प्रिंसिपल के लिये आने वाले आवेदनों की एक प्रति एमडीयू को भी जानी चाहिये थी जो नहीं भेजी गयी। भर्ती के लिये होने वाले साक्षात्कार में एमडीयू का एक नुमायंदा बैठना जरूरी है, जब वहां आवेदन की प्रति ही नहीं पहुंची तो नुमायंदा कैसे आयेगा ? भर्ती प्रक्रिया की एपरूअल कॉलेज प्रबंधन कमेटी से भी होनी चाहिये। इस कमेटी की मीटिंग साल में एक बार जरूर होनी चाहिये जो गत 5 वर्ष से नहीं हुई है। इसकी मीटिंग इस लिये नहीं हो पा रही क्योंकि इसका गठन ही एआईसीटीई व एमडीयू के मानकों के अनुरूप नहीं है। यानी कि इस कॉलेज की प्रबन्धन कमेटी/गवर्निंग बॉडी भी नकली ही है। खबर लिखते-लिखते पता चला है कि एमडीयू ने आवेदन मांगे जाने वाले विज्ञापन को ही रद्द कर दिया है। अन्य कमियों के अलावा यह विज्ञापन किस की ओर से जारी किया गया यानी आवेदन कौन मांग रहा है, कोई पता नहीं, जबकि कायदे से आवेदन मांगने का अधिकार डीएवी प्रबन्धन कमेटी के प्रावधान को है।

नीलम गुलाटी प्रिंसिपल पद के लिये अपनी फ़र्जी डिग्रियों का इस्तेमाल तो कर ही रही हैं, अनुभव भी 21 साल का बता रही हैं। यानी जब वे फ़ीस की पर्चियां काटती थी, साथ-साथ पढाई का पाखंड भी कर रही थी उस काल को भी वे अपने अनुभव में गिनती हैं।

सन् 2013 के बाद से कॉलेज का ऑडिट नहीं हुआ है और वह ऑडिट भी नीलम के पति रवि गुलाटी ने किया था जो कायदे से इसके लिये अधिकृत नहीं हैं। ऑडिट न होने का मतलब साफ़ समझा जा सकता है कि घोटाले इतने जबरदस्त हैं कि कोई ऑडिटर (सीए) इन्हें ठीक करके अपना कैरियर दांव पर नहीं लगा सकता। ऐसे में ऑडिट न कराना ही बेहतर समझा जा सकता है। घोटाले करने में माहिर कॉलेज प्रबन्धन छात्रों से फ़ीस वसूली में भी घोटालों की कमी नहीं छोड़ रहा है। काऊंसिल एवं यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत फ़ीस से कई-कई गुणा अधिक फ़ीस दो नम्बर में वसूली जाती है। इसी दो नम्बर के पैसे से एआईसीटीई व एमडीयू के भ्रष्टाचारियों को पाला-पोसा जाता है। इस सब के बाद आर्य समाज की पताका लिये समाज सुधार की बातें करते हैं ये नकली आर्यसमाजी।

अगवानपुर के स्कूल पर ठोका ताला, निकम्मी सरकार से निपटने को अब स्कूली छात्र उतरने लगे मैदान में

फ़रीदाबाद (म.मो.) बरसों तक सरकार के लारे-लप्पे देखने के बाद दिनांक 21 अगस्त को गांव अगवानपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के छात्र संघर्ष के मैदान में उतर पड़े। उन्होंने प्रात: स्कूल खुलने से पूर्व ही मेन गेट पर ताला जड़ दिया और जम कर सरकार विरोधी नारेबाज़ी की। प्राधानाचार्य अंजू छाबड़ा व स्टाफ़ के कहने से जब छात्र नहीं माने तो डीईओ (ज़िला शिक्षाधिकारी) सतेंद्र कौर को मोके पर आना पड़ा। उनके वहां पहुंचने से पहले आस-पास के गांवों के प्रिंसिपल तथा पल्ला थाने की पुलिस भी पहुंच गयी थी।

संघर्ष पर उतरे छात्र न तो नौकरी मांग रहे थे न कोई वेतन या भत्ता मांग रहे थे। ये तो केवल वही कुछ मांग रहे थे जिसको देने का ढोल, सरकारी भोंपू दिन-रात, पीटते रहते हैं। स्वच्छता अभियान के नाम पर अरबों का टैक्स वसूल चुकी सरकार के इस स्कूल में शौचालय तक की व्यवस्था न के बराबर है। इसमें सबसे अधिक कठिनाई लड़कियों को होती है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढाओ का ढोल पीटने वाली सरकार को यह बिल्कुल नज़र नहीं आता।

कक्षा में बैठने के लिये न तो बेंच हैं न पंखे और न ही बिजली की व्यवस्था। ऐसे में कोई बच्चा क्या पढाई कर पायेगा ? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित सहित कई विषयों के अध्यापक ही नहीं हैं। जब पढाने वाला ही कोई नहीं होगा तो बच्चे पढेंगे क्या ? जब परिणाम ज़ीरो प्रतिशत आयेगा तब सरकार जांच आयोग बैठायेगी जो अंधी बहरी सरकार को ज़ीरो प्रतिशत परिणाम के कारण बतायेगी। हर साल यही होता है लेकिन सरकार समाधान करने में कोई रुचि नहीं ले रही।

मौके पर पहुंची डीईओ ने सब कुछ ठीक करने का आश्वासन देकर छात्रों को शान्त किया और ताला खुलवा कर स्कूल चालू कराया। छात्रों के अनुसार जब भी वे अपनी इन मांगों को प्रधानाचार्य छाबड़ा के सामने रखते तो वे उन्हें धमकाती व डराती तथा दुर्व्यवहार करती। इसलिये छात्रों की मांग उन्हें वहां से हटाने की भी थी। शहर में रहने वाली अंजू छाबड़ा कौन सी दिल्ली बॉर्डर व यमुना किनारे बसे इस गांव में तैनात रह कर राज़ी थी। वह भी चाहती थी कि किसी तरह यहां से पिंड छूटे। छात्रों की मांगों को जायज ठहराने की अपेक्षा अंजू ने अपने ही स्कूल के एक प्राध्यापक आज़ाद सिंह पर छात्रों को भड़काने व उकसाने का आरोप लगाया है। यदि यह आरोप सही है तो आज़ाद सिंह बधाई के पात्र हैं जिन्होंने छात्रों को अपने अधिकारों के लिये संघर्ष का रास्ता दिखाया। इसी एक स्कूल में नहीं बल्कि अब छात्र जगह-जगह अपनी मांगों के लिये संघर्ष करने लगे हैं। पिछले दिनों पृथला गांव की छात्राओं ने भी राजमार्ग जाम करके संघर्ष का रास्ता दिखाया था। स्कूली छात्र भी अब समझने लगे हैं कि यह झूठे व मक्कारों की सरकार बिना लड़े उन्हें शिक्षा का अधिकार देने वाली नहीं है।

फ़ोन पर पूछने पर डीईओ ने बताया कि ग्रामीण स्कूलों में स्टाफ़ की कमी है। इसके लिये उन्होंने सरकार को लिखा है लेकिन फ़िलहाल वे इधर-उधर से अस्थाई ड्यूटी पर शिक्षकों को वहां भेजेंगी। लेकिन यह भी केवल लारा-लप्पा ही है। फ़ाल्तू स्टाफ़ तो कहीं है ही नहीं, वे भेजेंगी कहां से। जाहिर है कहीं और का घटा कर यहां कुछ समय के लिये भेज कर खानापूर्ति कर देंगी। एक सवाल का जवाब में डीईओ ने बताया कि यह सही है कि अंग्रेजी की मासिक परीक्षा के लिये 13 छात्रों के पास केवल एक ही प्रश्न पत्र था। इसके लिये प्रिंसिपल ने तो बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) मुनीष चौधरी को छात्रों की सही संख्या भेजी थी परंतु बीईओ की लापरवाही के चलते यह गड़बड़ हुई है। इसके लिये उनकी जवाब तलबी की जा रही है। लेकिन जिसके सिर पर केन्द्रीय मंत्री किशनपाल का हाथ हो वह ऐसी जवाब तलबियों की क्या परवाह करेगी।

वास्तव में ये सभी समस्यायें एक अगवानपुर स्कूल की नहीं हैं। हरियाणा भर के लगभग 90 प्रतिशत स्कूल ऐसी ही दुर्दशा के शिकार हैं और ये तब तक शिकार बने ही रहेंगे जब तक छात्र व अभिभावक मक्कारों की सरकार के विरुद्ध लामबंद होकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे।

केरल की मदद मोदी सरकार ने रोकी ?

गिरीश मालवीय

30 लाख भारतीय संयुक्त अरब अमीरात UAE में रहते और काम करते हैं जिनमें से 80 फीसदी केरल के हैं। UAE की तरक्की में इन लोगो का बड़ा योगदान है, खाड़ी देशों में भारत से साप्ताहिक रूप से 700 उड़ानें होती है। पिछले गणतंत्र दिवस पर उनके सुल्तान को मोदी जी ने मुख्य अतिथि बना कर बुलाया था। लिहाजा UAE की सरकार ने केरल में बाढ़ राहत के 700 करोड़ की मदद देने की पेशकश की है जिसे मोदी सरकार ने ठुकरा दिया है। अब चार दिन बाद यूएई के राजदूत से इस पेशकश का खंडन भी भारत सरकार ने करवा दिया।

अब विडम्बना देखिए कि यही मोदी सरकार एक ऐसा कानून पास कर देती है जिसमे ये प्रावधान है कि राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी।

भाजपा सरकार ने 2016 के वित्त विधेयक जरिये विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन किया था, जिससे दलों के लिये विदेशी चंदा लेना आसान कर दिया गया। इस साल 1976 से ही राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच की संभावना को समाप्त करने के लिये इसमें आगे और संशोधन कर दिया गया लेकिन इस पर किसी ने आपत्ति नही ली।

मोदी सरकार कह रही है कि हम विदेशी मदद को स्वीकार नही करेंगे, क्योकि हमे घरेलू प्रयासों पर भरोसा है और केरल को खुद केवल 500 करोड़ की सहायता दे रहे हैं और इसे राष्ट्रीय आपदा भी घोषित नही कर रहे। वहीं स्वयं विदेशी चन्दा खाने से इन्हें कोई गुरेज नही है।